जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 27 संख्याः 27 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 26 अगस्त, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और फ्रेंच नैचुरलिस्ट व बायॉलजिस्ट, ज़ाँ बतीस्त लामार्क के जमाने से वैज्ञानिक हैरान हैं कि जिराफ को लम्बी गर्दन कैसे मिली। डार्विन का सिद्धांत अभी भी प्रचलित है पर "नैचुरल सलैक्शन" या "सैक्सुअल सलैक्शन" में से किस प्रक्रिया की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात पर इवोल्यूश्नरी (विकासवाद- संबंधी) वैज्ञानिकों में आज भी मतभेद है। चाइनीज़ अकैडमी ऑफ साईन्सेज़ के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुई एक रिसर्च, जो हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल "साईन्स" में छपी है, में सैक्सुअल सलैक्शन अवधारणा को महत्व दिया गया है। वर्तमान जिराफ के एक प्राचीन सम्बंधी, 1.7 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करने वाले डिस्कॉकरिक्स ज़ायज़ी, का एक जीवाश्म मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि लम्बी गर्दन "मेटिंग वॉर" जीतने में मदद करती होगी। साउथ अफ्रीका की युनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के बिहैवियरल इकॉलजिस्ट, रॉब सिमन्स, 1996 में सैक्सुअल सलैक्शन के पक्ष में तर्क दे चुके हैं। उस समय का प्रमुख स्पष्टीकरण था कि, लम्बी गर्दन से जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में सहायता मिली, जिससे वो पत्ती खाने वाले अन्य जानवरों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए और उनके सरवाइवल के अवसर बढ़ गए, इसलिए यह प्रवृति भावी पीढ़ियों में भी आ गई। नए शोध के मुख्य लेखक शी की वांग ने कहा, "संभवतया गर्दन लम्बी होने का मुख्य कारक लड़ाई हो सकता है, क्योंकि नर लड़ाई में अपनी लम्बी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं।" डिस्कॉकरिक्स ज़ायज़ी के जीवाश्मों के मॉर्फोलॉजिकल परीक्षण में सामने आया है कि, इन जानवरों के सिर की हड्डी हैलमैट जैसी मोटी थी और ये अक्सर सिर से सिर टकराकर लड़ते थे। इन प्राचीन जिराफों में सैक्सुअल सलैक्शन के दबाव की वजह से लम्बी गर्दन और सिर पर हैलमैट जैसी हड्डी विकसित हुई। फील्ड ऑब्ज़र्वेशन भी बताते हैं कि, मादा लम्बी गर्दन वाले नर को पसंद करती हैं। वैसे इस नए सिद्धांत से सभी सहमत नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया है कि, फिर मादा की गर्दन लम्बी क्यों होती है। नए शोध से भी जिराफ की लम्बी गर्दन के उद्विकास का मसला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, पर सैक्सुअल सलैक्शन में लम्बी गर्दन की भूमिका को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।

भाजपा अभी अनिश्चय की स्थिति में झारखण्ड में

भाजपा की दुविधा है, वह हेमन्त सोरेन की सरकार को गिराने में सक्रिय भूमिका रखे या सरकार को, उसमें मौजूद अन्तर विरोध के कारण स्वयं ही गिरने दे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन संकट में पड़ गई है क्योंकि चुनाव आयोग का मत है कि खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ "लाभ के पद" से संबंधित मामले में पर्याप्त प्रमाण है।

राज्य संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। राज्यपाल रमेश बैस विधानसभा से सोरेन को अयोग्य ठहराने से पहले संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं।

सोरेन का इस्तीफा होना तय है और गठबंधन के तीनों दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने गुरूवार को विचार विमर्श किया और तीन विकल्पों पर चर्चा की। पहला यह कि सोरेन इस्तीफा दें और फिर से तुरंत मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, विधानसभा की सदस्यता के बिना ही। दूसरा विकल्प है कि सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और तीसरा विकल्प है कि वे मध्यावधि चुनाव घोषित कर दें।

- **जैसा कि विदित ही है, "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट" के आरोप में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भंग करने की सिफारिश की है, अतः मु.मंत्री सोरेन की सरकार में अस्थिरता की स्थिति है।**
- **विधानसभा में सोरेन की पार्टी के तीस विधायक हैं। भाजपा के 26 तथा सोरेन की सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, के 23 विधायक हैं।**
- **भाजपा, कांग्रेस के 18 विधायकों में विभाजन भी करा सकती है।**
- **सोरेन के समक्ष अभी तीन विकल्प हैं या तो अपनी विधानसभा की सदस्यता त्याग कर छः महीने गैर सदस्य रहते हुए मु.मंत्री बने रहे, अथवा पत्नी कल्पना को मु.मंत्री बनवायें या मध्यावधि चुनाव करवायें।**

हालांकि इसी बीच झारखंड में "ऑपरेशन लोटस" की संभावना की भी चर्चा है पर भाजपा अभी तय नहीं कर पाई है कि उसे राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर सोरेन को पॉक्सी मुख्यमंत्री बनाने की अनुमति देकर यह इंतजार करना चाहिए कि गठबंधन सरकार अपने अन्तर्विरोधों से खुद ब खुद गिर जाए।

81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं और भाजपा के 26 विधायक है। कांग्रेस के 18 ए.जे.एस.यू. के दो भाकपा माले, राजद और भाकपा का एक-एक सदस्य है। कैश स्कैम केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी सोरेन की पार्टी के पास सहयोगी दलों की बदौलत पर्याप्त बहुमत है। दूसरी ओर भाजपा ज्यादा से ज्यादा 30 विधायकों का समर्थन जुटा सकती है कि जो कि पूर्ण बहुमत से 11 कम है। लेकिन पता चला है कि भाजपा के रणनीतिकार कांग्रेस विधायक दल में विभाजन कराने के लिए जोर-शोर से जुटे हुए हैं।

सोरेन के खिलाफ केस भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की इस शिकायत पर दर्ज किया गया है कि जून 2021 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम पर खनन लीज़ आवंटित करवाई थी। मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज़ का मामला चुनाव आयोग में लंबित है। उनके पिता शिबु सोरेन के खिलाफ भी लोकपाल कोर्ट में आय से अधिक सम्पत्ति का मामला चल रहा है।

'प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, पंजाब यात्रा के दौरान'

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रा ने प्रकरण की जांच करके फिरोज़पुर के सीनियर सुपरिन्टैंडेंट पुलिस को इस चूक के लिये जिम्मेवार ठहराया

-जाल खबांता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इन्दू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले पैनल ने फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस उपअधीक्षक को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में खामी का जिम्मेवार ठहराया है। कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की 5 जनवरी की यात्रा के दौरान पर्याप्त फोर्स होने के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं की गई थी।

जस्टिस इंदू मल्होत्रा उस कमेटी की मुखिया थी जिसने 5 जनवरी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा खामी की जांच की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री का काफिला फिरोज़पुर जाते समय फ्लाइओवर पर फंस गया था। प्रधानमंत्री फिरोज़पुर एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा खामी के लिए 12 जनवरी को समिति गठित की थी।

- **रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि, हालांकि, एस.एस.पी. के पास पर्याप्त पुलिस फोर्स थी, तथा उन्हें प्रधानमंत्री की यात्रा से दो घण्टे पहले सूचना भेज दी गई थी, वे सुरक्षा प्रदान करने से चूक गये।**
- **जैसा कि, विदित ही है, प्र.मंत्री का काफिला, फ्लाई-ओवर पर बीस मिनिट तक असुरक्षित खड़ा रहा था, जब प्र.मंत्री फिरोज़पुर जा रहे थे, आम सभा को संबोधित करने।**
- **सुप्रीम कोर्ट यह रिपोर्ट सरकार को भेजेगा उचित कार्यवाही के लिये।**

चीफ जस्टिस एन.वी.रमना और जस्टिस सूर्यकान्त व हिमा कोहली की बैंच रिपोर्ट देख रही है, जिसमें कमेटी ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की "ब्लू बुक" की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाए।

रिपोर्ट कहती है कि, फिरोज़पुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानून व्यवसाय बनाए रखने की ड्यूटी पूरी करने में असफल रहे। पर्याप्त फोर्स होने के बाद भी वे सुरक्षा व्यवस्था ही कर पाए जबकि उन्हें प्रधानमंत्री के उस मार्ग पर आने को दो घंटे पहले सूचना दे दी गई थी।

कोर्ट का कहना है कि वे यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी के पास भेजेंगे जो इस पर उचित कार्यवाही करेगी। बैंच ने कहा कि रिपोर्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक सुधारों व उपायों के बारे में भी बताया गया हैं। इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व वाली टीम नैशनल इन्वैस्टिगैटिंग एजेंसी के डी.जी.पी. या उनके प्रतिनिधि है, जो महानिरीक्षक के समकक्ष पद का हो, चड़ीगढ़ पुलिस के महानिदेशक, पंजाब पुलिस (सुरक्षा) के अतिरिक्त महानिदेशक और पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार!

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के एक संगठन "लॉयर्स वॉइस" ने याचिका दायर की थी तथा सुरक्षा खामियों की पृथक जांच की मांग के साथ यह मांग भी की थी कि भविष्य में ऐसा फिर न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

दूध पर संकट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और 8 करोड़ किसानों की बदौलत प्रति वर्ष 20 करोड़ टन दूध उत्पादित होता है, और अधिकांश दूध की खपत यहीं होती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पाद मुश्किल होता जा रहा है और इसकी खरीद और महंगी होती जा रही है, मुख्यत: जलवायु परिवर्तन की वजह से।

- **भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है पर विशेषज्ञों का कहना है कि, क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत के दुग्ध उत्पादन में 11 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।**

वनस्पतियों को मुरझा देने वाली गर्मी इस वर्ष जल्दी पड़ गई और साधारण से अधिक समय तक रही। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने माना कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अडानी ग्रुप की प्रगति उन ऋणों पर टिकी है जो सरकारी बैंक उन्हें दे रहे हैं'

-जाल खबांता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। कांग्रेस ने गुरूवार को इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि गौतम अडानी जैसे सरकार के कुछ मित्रों को जो ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उन्होंने देश को राष्ट्रीय ऋण दायित्वों के संदर्भ में सर्वाधिक चिन्तित स्थिति में ला दिया हैं।

पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रैस कांफ्रेंस में बताया कि यह एक गंभीर मसला है क्योंकि वर्ष 2022-23 के अन्त में केन्द्र सरकार पर आन्तरिक और बाह्य ऋणों के बकाया और दायित्वों करीब 152.17 लाख करोड़ थे, जबकि वर्ष 2013-14 में ये 55.9 लाख करोड़ ही थे। सामान्य शब्दों में प्रति व्यक्ति ऋण भार 43 हजार 124 से 1.09 लाख हो गया हैं।

उन्होंने अडानी ग्रुप की चौंकाने वाली ऋण स्थिति पर न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट्स द्वारा हाल ही गई एक रिपोर्ट का हवाला दिया

- **कांग्रेस के प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म, की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरोप लगाया कि, अडानी ग्रुप पर 2 लाख 30 हजार करोड़ रू. का ऋण है, अडानी परिवार ने नये प्रोजैक्ट लगाने में स्वयं का पैसा बहुत कम लगाया है और बैंक के उधार से ही नये-नये प्रोजैक्ट खरीदे हैं।**
- **अडानी ग्रुप ने अप्रेल 2020 से जून 2022 की अवधि में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 48 हजार करोड़ रू. का ऋण प्राप्त किया। एक ही पार्टी को इतना बड़ा ऋण देना बैंक के लिये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि, अगर यह पार्टी फेल हो गयी तो बैंक को डूबने से बचाना बहुत मुश्किल होगा।**
- **कांग्रेस का आरोप है, गौतम अडानी को इतनी बैंक सुविधाएं इसलिये मिलीं, क्योंकि वे प्र.मंत्री मोदी के मित्र हैं।**

क्योंकि अडानी ग्रुप का कुल सकल ऋण करीब 2.3 ट्रिलियन (2 लाख, 30 हजार करोड़ रूपए है)। रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि नए अथवा असम्बद्ध व्यवसायों, जिनमें पर्यावरण,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन आतंकी मारे गये

श्रीनगर, 25 अगस्त (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास गुरुवार को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम तीन सशस्त्र घुसपैठिये मारे गये।

- **सुरक्षाबलों ने एल.ओ.सी. पर आतंकियों को घुसपैठ करते देख इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, सुरक्षाबलों ने अपनी चाकचौबंदी से पिछले चार दिनों में आतंकी घुसपैठ की तीन कोशिशों को नाकाम किया है।**

आधिकारिक सूत्रों आज यहां बताया कि सुरक्षाबलों ने घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है।

जवानों ने उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में सीमा के पास संदिग्ध हरकत देखी।

सुप्रीम कोर्ट के प्रति आक्रामक रूख रखने वाले तमिलनाडू के वित्त मंत्री को पूर्व उप राष्ट्रपति नायडू का समर्थन मिला

वित्त मंत्री पी.टी.आर. ने कहा था कि, यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि, वह राज्य सरकारों को आदेश दे कि, राज्य सरकार अपना पैसा कैसे खर्च करें

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। तमिलनाडु के जाने माने और अपने विषय के विशेषज्ञ वित्त मंत्री पी. त्यागराजन जो तीखे बयानों के लिए चर्चित हैं, पर उनके विवादास्पद बयान पर इस चौतरफा हमले हो रहे हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके तीखे बयान पर तल्ख टिप्पणी है। गौरतलब बात यह है कि राजन की चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वैकेंया नायडू ने उन्हें शाबाशी दी है।

मदुरै के ये डी.एम. के. (द्रमुक) नेता, जो पी.टी.आर. नाम से प्रसिद्ध हैं, उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गये थे, जब उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जिन्हें "फ्रीबीज" कहा गया है, पर निर्देश देने के केन्द्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पर सवालिया निशान लगाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ्रीबीज के मुद्दे को हाथ में लेने के लिये, न्यायपालिका पर की गई पी.टी.आर. की टिप्पणियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति दर्शाई थी तथा कहा था कि वह डी.एम.के. के बयानों को देख रहा है। न्यायालय ने कहा था कि ये बयान सही नहीं है।

- **पूर्व उप राष्ट्रपति नायडू ने भी पी.टी.आर. का समर्थन करते हुए जोड़ा कि, किसी भी कानून की व्याख्या करानी हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है, पर राज्य सरकार की, क्या नीति हो और कितना पैसा किस स्कीम पर खर्च करना है, यह राज्य सरकार के दायरे की बात है।**
- **पी.टी.आर. ने तो केन्द्रीय सरकार पर और भी गंभीर कटाक्ष करते हुए कहा था कि, तमिलनाडू की सरकार राज्य की इकॉनमी को बेहतर मैनेज कर रही है, तथा कथित "रेवड़ियां" बांटने के बावजूद तमिलनाडू की ग्रोथ रेट, केन्द्रीय सरकार से बेहतर है, तमिलनाडू में महंगाई कम है, आदि, आदि, अतः केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडू सरकार पर कटाक्ष करना उचित नहीं।**

तमिलनाडु के वित्त मंत्री, जो हर समय शोधपूर्ण जानकारी, विषय तथा आक्रामकता से लैस रहते हैं, के तेवर, स्वर तथा शब्द-चयन अप्रिय तथा अपमानजनक लग सकता है तथा कुछ लोग यह भी महसूस कर सकते हैं कि उनके बयानों से बौद्धिक अहंकार की गंध आती है। लेकिन जो आँकड़े उन्होंने प्रस्तुत किये, में ऐसे बाध्यकारी तर्क समाहित थे, जो उनके इस दावे का समर्थन कर रहे थे कि तमिलनाडु ने केन्द्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों को अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के मामले में पीछे छोड़ दिया है, इसलिये तमिलनाडु को ऐसी सीख और उपदेश की जरूरत नहीं है कि वह अपना काम कैसे करे।

अब, जो चीज पी.टी.आर. तथा इस समय पूरे देश में बढ़ते जा रहे उनके समर्थकों एवं प्रशंसकों के लिये एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गेहूं का आटा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। कैबिनेट कमेटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स (सी.सी.ई.ए.) ने गुरुवार को गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक लगा दी क्योंकि मई के महीने में गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लग जाने के बाद, बेईमान व्यापारियों ने गेहूं के आटे का निर्यात शुरु कर दिया था।

- **केन्द्र सरकार की कैबिनैट कमेटी ने गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध होने की वजह से व्यापारी गेहूं का आटा निर्यात करने लगे थे।**

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम की जरुरत इसलिये पड़ी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के आटे की माँग बढ़ने के कारण, देश में भी गेहूं के आटे की कीमतों में एकाएक उछाल आ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)